भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4313

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं और डिजिटल मीडिया के विकास के लिए सरकारी सहायता

4313. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं, पत्रकारों और डिजिटल सामग्री निर्माताओं को विशेष रूप से ओडिशा जैसे राज्यों में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या वित्तीय और नीतिगत उपाय किए गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन पहलों के तहत आवंटित और संवितरित की गई धनराशि कितनी है और किस तरह से इन उपायों से क्षेत्रीय मीडिया उद्योग को लाभ हुआ है;

(ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओडिशा की क्षेत्रीय फिल्मों और डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन पहलों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) सरकार किस तरह से जिम्मेदार सामग्री का प्रसार करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मीडिया स्टार्टअप और स्वतंत्र पत्रकारों के विकास को सुनिश्चित कर रही है; और

(ङ) क्षेत्रीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में और वृद्धि करने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार **(**डीसीडीएफसी**)** स्कीम के अंतर्गत **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम** (एनएफडीसी) ओडिशा सहित विभिन्न क्षेत्रों के सभी फिल्म निर्माताओं को अनेक भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता

है। एनएफडीसी नवोदित निर्देशक को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और ओडिया सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के सह-निर्माण को सहायता प्रदान करता है। पिछले 5 वर्षों में फिल्म निर्माण संबंधी कार्यकलापों को सहायता देने के लिए 93.64 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मंजूर की गई है जिससे पहली बार फिल्म बनाने वालों को सशक्त और सह-निर्माणों को सुकर बनाकर क्षेत्रीय मीडिया उद्योग के विकास का संवर्धन हुआ है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया सिने हब (आईसीएच) की स्थापना की है ताकि वे दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अपनी फिल्मों को बढ़ावा दे सकें। आईसीएच किसी भी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किसी प्रतियोगिता खंड में चयनित फिल्मों या अकादमी पुरस्कारों में विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत भारत के आधिकारिक नामांकन को प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार मीडिया और मनोरंजन सहित विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रमुख योजनाओं को लागू कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) शुरू किए, ताकि उत्कृष्ट स्टार्टअप और इकोसिस्टम एनेब्लर्स को मान्यता दी जा सके और उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों में विभिन्न श्रेणियों में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सोशल मीडिया आउटरीच, ऑफ-लाइन और ऑनलाइन विज्ञापन, व्यक्तिगत क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ और वेबिनार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा पुरस्कारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इकोसिस्टम के हितधारकों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नालॉजी (आईआईसीटी) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाना, भारतीय और वैश्विक उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करना, एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र के लिए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना और छोटे व्यवसायियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। आईआईसीटी एक स्वतंत्र, उद्योग द्वारा संचालित संस्था है जो उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

*****